



कृषक समाचार

भारत कृषक समाज का मासिक मुख पत्र

कृषक समाचार की 32,000 प्रतियां सन् 1960 से हर महीने छापकर सदस्यों को भेजी जाती हैं

वर्ष 63

दिसंबर, 2018

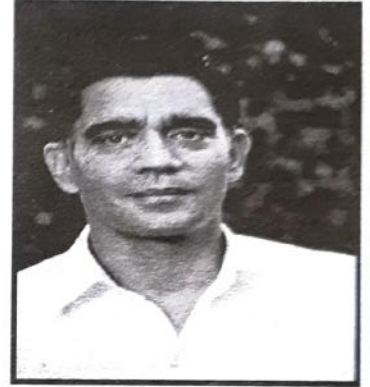
अंक 12

कुल पृष्ठ 8

सभापति का पत्र :

हर कोई डेस्क वाली नौकरी और साफ रहने वाले काम करना चाहता है और जो स्कूल में पढ़ चुके हैं वे खेतों में काम नहीं करना चाहते।

कौशल विकास, विशेषकर कृषि कौशल का इतना विकास नहीं हुआ है कि कृषि क्षेत्र में वास्तविक लाभ कमाने में सफलता मिले। एक ओर तो जहां युवा वर्ग के लिए रोजगार नहीं है तो दूसरी ओर आज भी अच्छे नलसाज, बढई, बिजली का काम करने वाले, मैकेनिक, इलैक्ट्रानिक मिस्त्री मिलने बहुत कठिन हैं।



कॉलेज डिग्री के एक भाग के रूप में निजी क्षेत्र में कौशल प्रशिक्षण देना पहली आवश्यकता होनी चाहिए। हम जर्मनी से सीख ले सकते हैं, उन्होंने इस कला में कुशलता प्राप्त कर ली है।

नए प्रकार के उपयोगी कार्यक्रम लागू करने से गरीबी हटाई जा सकती है और आजीविका में भी सुधार हो सकता है। बेहतर निर्णय लेने के लिए नीतिनिर्माताओं की क्षमता का निर्माण भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना ग्रामीण भारत के युवाओं को योग्य और निपुण बनाना।

ग्रामीण भारत के जीवनस्तर, स्वास्थ्य और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता है। सरकार लगातार शहरी आधारभूत सुविधाओं में सुधार करती है, यही एक कारण है कि गांव के प्रतिभावान और उद्यमी, परिश्रमी युवा गांव छोड़ रहे हैं और वे नौकरी और बेहतर आजीविका / रहन सहन के लिए शहरों की ओर प्रस्थान कर रहे हैं।

जो लोग गांव में रह रहे हैं, उनमें से अधिकांशतः कहीं ओर नौकरी पाने के योग्य नहीं होते हैं। हमें गांव में भी ढांचागत सुविधा क्षेत्र में इस प्रकार से नए निवेश करने होंगे कि नगरों जैसी सुविधाएं गांव में उपलब्ध कराकर कृषि पर लोगों की प्रत्यक्ष निर्भरता की संख्या को कम किया जा सके।

नए उपायों का यह उचित समय है, जैसे कि सरकार केवल निम्नतम श्रेणी के कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन पर ही वेतन आर्थिक सहायता का भुगतान करे। ऐसा करने से न केवल लोगों

को आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा अपितु औपचारिक (सुव्यवस्थित) अर्थव्यवस्था के निर्माण में लोगों की भागीदारी में वृद्धि भी होगी।

अनियमित क्षेत्रों में कानूनी अधिसूचनाओं को जारी करके वेतन नहीं बढ़ाए जाते। वास्तविक मजदूरी में वृद्धि होगी, यदि वेतन की सब्सिडी की योजना आरंभ की जाए। उत्कृष्ट आंकड़े, विश्लेषण और पूर्वानुमानों की कमी होने के कारण नीतिनिर्माता भी सही और सटीक निर्णय नहीं ले पाते हैं।

— अजय वीर जाखड़
अध्यक्ष, भारत कृषक समाज
@ajayvirjakhar